पाठ - 3
नियोजित विकास की राजनीति

1/10/2022

PANKAJ
Page No.:
Date: / /

(1.) राजनीतिक फैसले और विकास :—

⇒ लौह अयस्क के अधिकांश भण्डार उड़ीसा राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में हैं जिनका दोहन होना अभी शेष है।

⇒ इस्पात की विश्वव्यापी माँग बढ़ने से निवेश की दृष्टि से उड़िसा एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में उभरा है। इस राज्य की सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित माँग से लाभ प्राप्त करना चाहा।

⇒ उड़ीसा सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय इस्पात - निर्माताओं व राष्ट्रीय स्तर के इस्पात - निर्माताओं के साथ सहमति - पत्र पर हस्ताक्षर किए। आदिवासियों को डर है कि यहाँ उद्योग स्थापित हो गए तो उन्हें घर से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी।

⇒ पर्यावरणविदों को इस बात का भय है कि खनन व उद्योग से पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होगी वहीं केन्द्र व राज्य सरकार को लगता है कि उड़ीसा के लौह उत्पादक क्षेत्रों में उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गयी तो इससे एक गलत परम्परा की शुरुआत होगी व देश में पूँजी निवेश में बाधा उत्पन्न होगी।

(i) राजनीतिक टकराव :—

⇒ किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार के फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम इन फैसले पर विरोधियों की स्वीकृति होनी चाहिए।

⇒ खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना आवश्यक है परन्तु अंतिम निर्णय निश्चित रूप से जन प्रतिनिधियों को ही लेना चाहिए।

⇒ स्वतंत्रता के बाद देश में ऐसे कई फैसले लिए गए। सभी फैसले परस्पर आर्थिक विकास के एक मॉडल या 'विजन' से जुड़े हुए थे।

⇒ भारत के विकास का अर्थ आर्थिक संवृद्धि तथा आर्थिक सामाजिक - न्याय ही है। इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति तथा किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। सरकार को इस मसले पर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना था।

(ii) विकास की धारणाएँ :—

⇒ जनता के विभिन्न वर्गों के लिए 'विकास' के अर्थ अलग होते हैं। इस कारण 'विकास' से जुड़ी कोई भी 'चर्चा' विवादों से दूर नहीं होती।

⇒ स्वतन्त्रता से पूर्व लोग 'विकास' की बात आते ही 'विकास' का पैमाना पश्चिमी देशों को मानते थे। विकास का अर्थ था अधिक से अधिक आधुनिक होना तथा आधुनिक होने का अर्थ — पश्चिमी औद्योगिक देशों के समान होना।

⇒ स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला उदारवादी - पूँजीवादी मॉडल था। यूरो के अधिकांश देशों और संयुक्त राज्य अमरीका में यही मॉडल अपनाया गया था।

⇒ उस समय भारत में अनेक लोग विकास के सोवियत मॉडल से बहुत अधिक प्रभावित थे।

⇒ सभी एक ही बिन्दु पर सहमत थे कि विकास का कार्य निजी हाथों में नहीं सौंपना चाहिए और सरकार के लिए यह अति आवश्यक है कि वह विकास की एक योजना तैयार करे।

(iii) नियोजन :—

⇒ अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को सन् 1940 और सन् 1950 के दशक में सम्पूर्ण विश्व में जनसमर्थन प्राप्त हुआ था।

⇒ सोवियत संघ ने सन् 1930 और सन् 1940 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच बहुत अधिक आर्थिक प्रगति की थी। यह सब नियोजन से ही सम्भव हुआ था। इस प्रकार योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था।

⇒ सन् 1944 में भारत में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। जिसे 'बॉम्बे प्लान' के नाम से जाना जाता है। 'बॉम्बे प्लान' की इच्छा थी कि सरकार औद्योगिक व अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए।

⇒ इस प्रकार दक्षिणपंथी और वामपंथी सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था के मार्ग पर चलकर आगे बढ़े। देश स्वतन्त्र होते ही योजना आयोग अस्तित्व में

PANKAJ
Page No.:
Date : / /

आया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बनें।

(2.) ☆ **योजना आयोग** :— योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित बाकी आयोगों की तरह नहीं है। योजना आयोग की स्थापना, 15 मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे-साधे प्रस्ताव के जरिए की। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे।

(15 मार्च 1950) स्थापना

योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।

⇒ भारत का योजना आयोग, भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनायें बनाना था।

यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है।

⇒ 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) किया गया।

NITI — National Institution for Transforming India Aayog

⇒ अन्य कार्य :— (i) देश के संसाधनों का आकलन करना।
(ii) योजनाओं की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन करना।
(iii) आर्थिक विकास को बाधित करने वाले कारकों की पहचान करना।
(iv) आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना

⇒ योजना आयोग के सदस्य कौन थे :— वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री, सूचना प्रौद्योगिक मंत्री, कानून मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और योजना मंत्री शामिल थे